

दैनिक

भारत सरकार के डीएवीपी व राज्य सरकार द्वारा विज्ञापन के लिए मान्यता प्राप्त

नजरिया खबर



पेज-03

RNI:UTTHIN/2008/25052

वर्ष:18

अंक: 07

देहरादून, रविवार 06 जुलाई, 2025

पृष्ठ: 08

मूल्य: 1/रु. प्रति

न्यूज डायरी

प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी



देहरादून। उत्तराखंड के चारधाम और यात्रा मार्गों पर शनिवार को बादल मंडराने और हल्की बौछारें पड़ने के आसार हैं। रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून और नैनीताल सहित आसपास के क्षेत्र में गरज-चमक के साथ तीव्र बौछारें पड़ सकती हैं। देहरादून में धूप और बादलों की आंख-मिचौली चल रही है। गत दिवस बारिश से राहत मिली लेकिन तेज धूप के चलते तापमान में बढ़ोतरी हुई और गर्मी ने बेहाल कर दिया। देहरादून के आसपास के क्षेत्र में भी बादलों की मिचौली चलती रही और देर रात तक बादल छाने की कारण बारिश के आसार भी बन रहे।

पैराफिट से टकराई स्कूटी, खाई में गिरी युवती, हालत गंभीर

देहरादून। देहरादून-मसूरी रोड पर एक स्कूटी अनियंत्रित होकर गज्जी बैंड के पास पैराफिट से जा टकराई। इस हादसे में स्कूटी पर पीछे बैठी युवती खाई में जा गिरी। जिससे युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव अभियान चलाया गया। जानकारी के मुताबिक, उत्तरकाशी के मोरी तहसील के हड़वाड़ी निवासी नवीन पुत्र विक्रम सिंह और प्रिया निवासी कोटगांव, मोरी (उत्तरकाशी) स्कूटी से पुरोला से देहरादून की ओर रहे थे। जैसे ही वो गज्जी बैंड के पास पहुंचे, तभी चालक का संतुलन बिगड़ गया और स्कूटी पैराफिट से टकरा गई।

मुख्यमंत्री ने टनकपुर से कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले दल को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

देहरादून (नजरिया खबर ब्यूरो)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को टनकपुर स्थित पर्यटन आवास गृह से कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने यात्रियों का पारंपरिक रूप से स्वागत किया तथा उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े स्मृति चिह्न भेंट किए।

मुख्यमंत्री ने 11 राज्यों से आए सभी श्रद्धालुओं से संवाद कर उनका देवभूमि उत्तराखंड में हार्दिक स्वागत किया। मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता, यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मिक और आध्यात्मिक जागरण का मार्ग है। उन्होंने कहा श्रद्धालु इस अद्वितीय यात्रा के सहभागी बनकर केवल यात्रा नहीं, बल्कि समर्पण की अनुभूति लेकर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की पवित्र धरती के कण-कण में भगवान शिव का वास है। यह यात्रा अब केवल भौगोलिक मार्ग नहीं रही, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और दृढ़ संकल्प से यह सीमाओं को लांघते हुए शिव से साक्षात्कार का सशक्त माध्यम बन गई है। पहले जिस यात्रा में सात



मानसरोवर यात्रा दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते सीएम।

दिन या उससे अधिक का समय लगता था, अब वह कुछ ही घंटों में संभव हो सकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार इस यात्रा को सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए पूरी तरह समर्पित है।

प्रत्येक पड़ाव पर स्वास्थ्य, आवास, भोजन, सुरक्षा और अन्य आवश्यक सुविधाएं सुदृढ़ की गई हैं, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने भगवान भोलेनाथ से सभी यात्रियों की सफल, मंगलमय और सुरक्षित यात्रा की कामना की। इस अवसर पर सभी श्रद्धालुओं ने चम्पावत वासियों के आत्मीय

व्यवहार के लिए आभार व्यक्त किया और यात्रा को स्मरणीय व सुरक्षित बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार की उत्कृष्ट व्यवस्थाओं की सराहना की। इस दौरान आयुक्त कुमाऊं मंडल दीपक रावत, आईजी आईटीबीपी और जन सम्पर्क अधिकारी कैलाश मानसरोवर यात्रा संजय गुंजियाल, पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं मंडल रिद्धिम अग्रवाल, प्रबंध निदेशक कुमाऊं मंडल विकास निगम विनीत तोमर, जिलाधिकारी चम्पावत मनीष कुमार, जिलाधिकारी पिथौरागढ़ विनोद गोस्वामी, पुलिस अधीक्षक चम्पावत अजय गणपति मौजूद थे।

सीएम धामी ने खटीमा में की धान रोपाई, किसानों के श्रम को किया नमन

खटीमा। खटीमा के नगरा तराई क्षेत्र में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को अपने खेत में धान की रोपाई कर किसानों के परिश्रम, त्याग और समर्पण को नमन किया। उन्होंने कहा कि खेतों में उतरकर पुराने दिनों की यादें ताजा हो गईं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नदाता न केवल हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, बल्कि वे हमारी संस्कृति और परंपराओं के संवाहक भी हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड



की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत "हुड़किया बौल" के माध्यम से भूमि के देवता भूमियां, जल के देवता इंद्र और छाया के देवता मेघ की वंदना भी की। मुख्यमंत्री के इस सांस्कृतिक जुड़ाव और कृषकों के साथ आत्मीय सहभाग ने क्षेत्रीय जनता को गहरे स्तर पर प्रेरित किया। मुख्यमंत्री धामी की यह पहल उत्तराखंड की ग्रामीण संस्कृति, कृषकों की अहमियत और पारंपरिक लोककलाओं के संरक्षण की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम है।

मुख्यमंत्री ने बाल संवाद कार्यक्रम में विद्यार्थियों से किया सीधा संवाद, खेल संस्कृति को मजबूत करने पर दिया जोर

देहरादून (नजरिया खबर ब्यूरो)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को पर्यटक आवास गृह, टनकपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चम्पावत जनपद के विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं से बाल संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत सीधा संवाद स्थापित किया।

कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यालयों में खेल गतिविधियों की प्रगति की जानकारी प्राप्त करना तथा खिलाड़ियों से उनकी आवश्यकताओं और सुझावों पर चर्चा करना रहा।

मुख्यमंत्री ने रा.इ.का. चम्पावत के गौरव, रा.इ.का. पाटी की प्रीति, रा.बा.



सीएम पुष्कर सिंह धामी।

इ.का. टनकपुर की कंचन, रा.इ.का. चम्पावत की मोनिका से बातचीत कर चौमेल के सागर एवं रा.बा.इ.का.

खेल सुविधाओं, संसाधनों और

प्रशिक्षण संबंधी जानकारी ली। विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि वे मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना से नियमित लाभान्वित हो रहे हैं, जिससे उनके खेल कौशल को संवारने में मदद मिल रही है।

मुख्यमंत्री धामी ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे पढ़ाई के साथ खेलों को भी बराबर महत्व दें। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड केवल देवभूमि नहीं, बल्कि खेलभूमि के रूप में भी अपनी पहचान बना रहा है। उन्होंने युवाओं को अमृतकाल का सारथी बताते हुए अनुशासन, समय

प्रबंधन और कठिन परिश्रम के महत्व पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को सशक्त मंच देने और खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

उन्होंने राज्य की खेल नीति और मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना जैसे प्रयासों को युवाओं के सर्वांगीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। इस अवसर पर चम्पावत, पाटी, चौमेल, टनकपुर और चमदेवल क्षेत्र के विद्यालयों के छात्र-छात्राएं और शिक्षण स्टाफ बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

संपादकीय

दलाई लामा को भारत रत्न

10 सदस्यीय समिति ने दलाई लामा के भारत रत्न नामांकन का समर्थन करते हुए हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया है और कथित तौर पर करीब 80 सांसदों के हस्ताक्षर एकत्र किए हैं, जिन्हें आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को सौंपने की योजना है। ईटी से बात करते हुए, राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार ने कहा, ष्मूह दलाई लामा के लिए भारत रत्न की मांग कर रहा है और उसने एक ज्ञापन पर 80 से अधिक सांसदों के हस्ताक्षर प्राप्त किए हैं, जिसे मंच 100 सांसदों के हस्ताक्षर एकत्र करने में सक्षम होने के बाद प्रस्तुत करेगा। ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वालों में विपक्षी दलों के सांसद भी शामिल हैं। तिब्बती मुद्दे के प्रति समर्थन जताने के लिए एक सर्वदलीय मंच ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने का आग्रह किया है। मंच ने सरकार से दलाई लामा को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने की अनुमति देने की भी अपील की है, यह कदम चीन के गुस्से का कारण बन सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, यह पत्र तिब्बत के लिए सर्वदलीय भारतीय संसदीय मंच द्वारा भेजा गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), बीजू जनता दल (बीजेडी) और जनता दल (यूनाइटेड) के सांसद शामिल हैं। मंच ने इस महीने अपनी दूसरी बैठक के दौरान प्रस्ताव के समर्थन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करने के बाद सरकार को यह अनुरोध प्रस्तुत किया। 10 सदस्यीय समिति ने दलाई लामा के भारत रत्न नामांकन का समर्थन करते हुए हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया है और कथित तौर पर करीब 80 सांसदों के हस्ताक्षर एकत्र किए हैं, जिन्हें आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को सौंपने की योजना है। ईटी से बात करते हुए, राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार ने कहा, ष्मूह दलाई लामा के लिए भारत रत्न की मांग कर रहा है और उसने एक ज्ञापन पर 80 से अधिक सांसदों के हस्ताक्षर प्राप्त किए हैं, जिसे मंच 100 सांसदों के हस्ताक्षर एकत्र करने में सक्षम होने के बाद प्रस्तुत करेगा। ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वालों में विपक्षी दलों के सांसद भी शामिल हैं। कुमार ने कहा कि हमने परम पावन दलाई लामा को भारत रत्न देने के लिए एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। कई सांसद आगे आए हैं और उनमें से कुछ ने अभियान का समर्थन करते हुए वीडियो संदेश भेजे हैं।

ऋषिकेश मेयर और कांग्रेसी नेता की बीच सड़क पर तीखी नोकझोंक, पुलिस बुलाई

ऋषिकेश (नजरिया खबर ब्यूरो)। ऋषिकेश में मेयर शंभू पासवान और कांग्रेस नेता दीपक जाटव के बीच तीखी नोकझोंक हुई। मामला इतना बढ़ गया था कि दीपक जाटव और स्थानीय लोगों ने मेयर शंभू पासवान का विरोध करते हुए उनके वाहन तक को घेर लिया था। दीपक जाटव और अन्य लोगों ने मेयर शंभू पासवान के वाहन को आगे नहीं जाने दिया, जिससे बात और ज्यादा बिगड़ गई।

आखिर में विवाद ज्यादा बढ़ा तो पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। पुलिस ने किसी तरह भीड़ को तितर बितर किया और मेयर शंभू पासवान को विरोधियों के बीच से बाहर निकाला। दरअसल, ये पूरा हंगामा परशुराम चौक से लेकर सत्संग भवन गंगानगर तक सड़क निर्माण का कार्य को लेकर हुआ। सड़क निर्माण के लिए जेसीबी कई दिनों से लगातार सड़क खुदान का काम कर रही है। लोगों का कहना है कि जेसीबी ने लिमिट से ज्यादा खुदाई की है। इस वजह से स्थानीय लोग काफी गुस्से में हैं। क्योंकि बारिश की वजह से गड्ढों में पानी भर रहा है और लोगों को कई



मेयर व कांग्रेसी नेता के बीच होती नोकझोंक।

प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मामले में दीपक जाटव स्थानीय लोगों के साथ मिलकर मौके पर पहुंचे और उन्होंने मेयर शंभू पासवान से वर्क आर्डर की कॉपी के साथ मौके पर निरीक्षण करने के लिए निवेदन किया। मेयर शंभू पासवान मौके पर पहुंचे तो लोगों ने समस्या को दिखाते हुए हल्ला करना शुरू कर दिया। इस दौरान वर्क आर्डर की कॉपी नहीं दिखाए जाने पर लोगों ने नाराजगी जताई। इसी बीच कांग्रेस नेता दीपक जाटव और मेयर के बीच तीखी नोकझोंक होने लगी। बात इतनी बढ़ी की सुरक्षा को देखते हुए मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा। किसी तरह

पुलिस ने भीड़ के बीच से मेयर शंभू पासवान को बाहर निकाला। दीपक जाटव ने आरोप लगाया कि यहां पर कार्य बिना वर्क आर्डर और बिना टेंडर के किया जा रहा है। अब तक लाखों रुपए की मिट्टी का उठान कर बेच दिया गया है। यदि मेयर साहब के मन में कोई आशंका नहीं थी तो वह मौके पर ही स्थिति को पेपर दिखाकर साफ करते और लोगों का गुस्सा शांत करते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वहीं मेयर शंभू पासवान ने बताया कि वर्क आर्डर की कॉपी ऑफिस में आकर देखी जा सकती है। बिना टेंडर और बिना वर्क आर्डर के कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व मशीन लर्निंग तकनीकी बनाम उन्नत अपडेट तेजी से परिष्कृत होते साइबर हमले व धोखाधड़ी

गोंदिया। वैश्विक स्तरपर पूरी दुनियाँ के आधुनिक प्रौद्योगिकी के बढ़ते क्रम में साइबर क्राइम के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जो बैंक अकाउंट साइबर क्राइम से बहुत आगे बढ़कर अबव्हाट्सएप मेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम सहित अनेकों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंच गए हैं, तो इधर किसी लिंक पर क्लिक किया उधर आप साइबर क्राइम का शिकार हुए, जैसी घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, जिसका संज्ञान लेकर अब यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी चौकन्ने हो गए हैं।

थोड़ा सा भी डाउट हुआ या ब्रिच ऑफ टर्म एंड कंडीशन हुए, तो तुरंत वह मीडिया प्लेटफॉर्म लॉक कर दिया जाता है। अभी अनेकों लोगों के व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट लॉक कर दिए गए हैं जिस पर ब्रिच आफ टर्मस एंड कंडीशंस लिखकर आ रहे हैं। एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र इस आर्टिकल के माध्यम से पूरी दुनियाँ के मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोगकर्ताओं से अपील करना चाहता हूँ कि अपने इंस्ट्रूमेंट का आति सावधानी से उपयोग करें, जिसके बारे में नीचे पैराग्राफ में चर्चा की गई है। हमारा वहमीडिया प्लेटफॉर्म भी बंद कर दिया जा सकता है, जिसमें हमारे बहुमूल्य डाटा या ग्रुप होते हैं, नया नंबर लेकर के वह प्लैटफॉर्म तो चालू किया जा सकता है परंतु उसके सारे



वैश्विक स्तरपर उन्नत व अपडेट होती साइबर ठगी-आरबीआई रिपोर्ट अनुसार भारत में बैंकों से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले घटे, परंतु रकम तीन गुना बढ़ी

डेटा उड़ जाते हैं,, इसलिए हमें साइबर क्राइम वालों को कोई मौका नहीं देना है और बहुत ही सावधानी के साथ अपने इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करना है। चूँकि पूरे विश्व के लिए साइबर अपराधों से जुड़ी कुल लागत और जोखिम का लगातार बढ़ना एक चुनौती है तथा उससे निपटने तात्कालिक अपडेट की आवश्यकता बढ़ गई है, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व मशीन लर्निंग तकनीकी बनाम उन्नत अपडेट तेजी से परिष्कृत होते साइबर क्राइम व धोखाधड़ी होने की संभावना है।

साथियों बात अगर हम वर्तमान समय में साइबर क्राइम के मामले तेजी से बढ़ाने की करें तो, कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिसमें नकली पुलिस, सीबीआई ऑफिसर बनकर लोगों को डिजिटल अरेस्ट किया गया और लाखों रुपये ठग लिए गए, इंटरनेट पर स्टोर जानकारी को एक्सेस करके ठग, लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। हालांकि, जिन लोगों के पास इंटरनेट नहीं है उनको भी ठग अपना शिकार बना ले रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि बिना

इंटरनेट के उनके पास हमारी जानकारी कैसे है? आज के दौर में अगर हम खुद को सुरक्षित नहीं रखते तो हम साइबर ठगी के शिकार हो सकते हैं, हम इससे बचने के लिए अगर ईमेल या किसी ऑनलाइन सर्विस का यूज कर रहे हैं तो कोशिश करें कि उसका पासवर्ड काफी मजबूत हो, गलती से भी अपने नाम, मोबाइल नम्बर या डेट ऑफ वर्थ को पासवर्ड न रखें, कोशिश करें कि हमेशा टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें, अगर हमको कोई अनजान मेल या मैसेज आता है और उसमें कोई लिंक दिया गया है तो गलती से भी उसको खोलने की कोशिश न करें, अपने फोन को हमेशा अपडेट रखें, अगर कोई सिक्योरिटी फीचर अपडेट आता है तो उसको जरूर करें, इससे हमारा फोन सुरक्षित रहता है। अगर हम इंटरनेट यूज नहीं करते हैं तो भी ठग आराम से हमको शिकार बना सकते हैं, दरअसल, इसके लिए वे हमारे डेटा को दूसरी जगह से उठाते हैं, इसमें वे सोशल साइट्स, अस्पताल, दुकान या फिर सरकारी ऑफिस आदि जगहों से डेटा लीक करते हैं या फिर किसी तरह निकालते हैं, फिर इस डेटा का

इस्तेमाल करके हमारे साथ ठगी के लिए करते हैं, कई लोगों का डेटा उनके किसी रिलेटिव के फोन से भी निकाल लिया जाता है। जो बेहद गंभीर बात है।

साथियों बात अगर हमसीबीआई के अभियान ऑपरेशन चक्र-5 की करें तो, सीबीआई ने साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट के मामलों से निपटने के लिए चल रहे प्रयासों के क्रम में, साइबर धोखाधड़ी में इस्तेमाल किए जा रहे खच्चर बैंक खातों के संबंध में पांच राज्यों में 42 स्थानों पर देशव्यापी तलाशी शुरू की है।

खच्चर खाता वह बैंक खाता है जिसका उपयोग अवैध गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है। यह अभियान ऑपरेशन चक्र-5 के तहत पांच राज्यों दृ राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में चलाया गया। जांच में पता चला है कि देश भर में विभिन्न बैंकों की सात सौ से अधिक शाखाओं ने लगभग साढ़े आठ लाख खच्चर खाते खोले हैं। एजेंसी ने बताया कि ये खाते या तो उचित केवाईसी मानदंडों या प्रारंभिक जोखिम मूल्यांकन के बिना खोले गए थे। तलाशी के दौरान, कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य, मोबाइल फोन, बैंक खाता खोलने के दस्तावेज, लेन-देन विवरण, केवाईसी

दस्तावेज जब्त किए गए हैं। सीबीआई ने खच्चर बैंक खाते खोलने के संचालन और सुविधा में उनकी संलिप्तता के लिए नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस पूरी कार्यवाही में बिचौलिए, एजेंट, खाताधारक और बैंक कर्म शामिल हैं।

साथियों बात अगर हम साइबर क्राइम को समझने की करें तो, साइबर अपराध एक सामान्य शब्द है जो कंप्यूटर, नेटवर्क या डिजिटल उपकरणों के किसी अन्य सेट का उपयोग करके की जाने वाली असंख्य आपराधिक गतिविधियों का वर्णन करता है। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व मशीन लर्निंग तकनीकी बनाम उन्नत अपडेट तेजी से परिष्कृत होते साइबर हमले व धोखाधड़ी, वैश्विक स्तरपर उन्नत व अपडेट होती साइबर ठगी-आरबीआई रिपोर्ट अनुसार भारत में बैंकों से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले घटे, परंतु रकम तीन गुना बढ़ी। पूरे विश्व के लिए साइबर अपराधों से जुड़ी कुल लागत और जोखिम से लगातार बढ़ने वाली चुनौतियों से निपटने तात्कालिक अपग्रेड की आवश्यकता बढ़ी।

लेखक — कर विशेषज्ञ स्तंभकार एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

लाखों की साइबर ठगी में सिविल इंजीनियर गिरफ्तार

देहरादून (नजरिया खबर ब्यूरो)। 62.50 लाख की साइबर ठगी के मामले में एसटीएफ की साइबर क्राइम थाना पुलिस ने एक सिविल इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कोयंबटूर तमिलनाडू से गिरफ्तार कर लिया है जो पीड़ितों को झांसे में लेने के लिए मैट्रीमोनियल साइट का प्रयोग किया करता था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, नवनीत सिंह द्वारा जानकारी देते हुये बताया गया कि एक प्रकरण जनपद नैनीताल निवासी पीड़ित ने दर्ज कराया, जिसमें शिकायतकर्ता ने स्वयं का मैट्रीमोनियल साइट संगम डॉट कॉम पर एकाउण्ट होने की बात कही गयी तथा इस साइट पर एक अन्जान युवती आरोपी रॉय का मैसेज प्राप्त होने की बात कही गयी, जिसके बाद व्हाट्सप पर मैसेज व कालिंग से कुछ समय तक बातचीत होना बताया, इस युवती ने स्वयं का कम्बोडिया में कपड़ों का व्यापार होने की बात बतायी गयी तथा पीड़ित से कुछ दिन बात होने के उपरान्त बेनोकोइन ट्रेडिंग एप्लीकेशन के बारे में जानकारी दी



मामले का खुलासा करते पुलिस अधिकारी।

गयी जिसके माध्यम से ऑनलाईन क्रिप्टो करेन्सी में निवेश किये जाने की बात कही गयी। जिसके बाद शिकायतकर्ता को व्हाट्सप के माध्यम से क्रिप्टो करेन्सी में निवेश करने के लिए उपलब्ध कराये गये विभिन्न बैंक खातों में लगभग 62.50 लाख रुपये की धनराशि धोखाधड़ी पूर्वक जमा करायी गयी।

मामले में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गयी। जांच के दौरान साइबर क्राइम पुलिस ने घटना में प्रयुक्त बैंक खातों व रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बरों व

व्हाट्सअप की जानकारी के लिए सम्बन्धित बैंकों, सर्विस प्रदाता कम्पनियों, मेटा कम्पनी से पत्राचार कर डेटा प्राप्त किया गया। प्राप्त डेटा के विश्लेषण से जानकारी मे आया कि साइबर अपराधियों ने घटना में पीड़ित से संगम डॉट कॉम मैट्रीमोनियल साइट पर दोस्ती करने के उपरान्त व्हाट्सप पर मैसेज व कालिंग के माध्यम से बेनोकोइन एप पर ऑनलाईन क्रिप्टो ट्रेडिंग में निवेश कर अधिक लाभ कमाये जाने के नाम पर विभिन्न बैंक खातों में धनराशि स्थानान्तरित करवायी गयी। जांच के

दौरान साइबर थाना पुलिस ने मुकदमें में प्रकाश में आए बैंक खातों तथा मोबाइल नम्बरों का सत्यापन किया गया।

आरोपी ने मैट्रीमोनियल साइट संगम डॉट कॉम पर महिलाओं के नाम की फेक आईडी बनाकर पीड़ितों को रिक्वेस्ट भेजी जाती थी, तथा स्वयं का कपड़ों का बिजनेस कम्बोडिया में होना बताया जाता था, कुछ समय तक मैट्रीमोनियल साइट्स पर ही बातचीत किये जाने के उपरान्त आरोपी ने अपना व्हाट्सप नम्बर पीड़ितों के साथ शेयर किया जाता था। जिसके बाद व्हाट्सप पर मैसेज व कॉलिंग के माध्यम से ही पीड़ितों को फर्जी बेनोकोइन एप के माध्यम से क्रिप्टो करेन्सी में निवेश कर अत्यधिक लाभ प्राप्त किये जाने की बात कही जाती थी, तथा क्रिप्टो करेन्सी में निवेश किये जाने के लिए व्हाट्सप के माध्यम से ही अलग-लग बैंकों के खाते प्रदान किया जाते थे, जिसमें पीड़ितों द्वारा लालच में आकर भारी भरकम धनराशि निवेश कर दी जाती थी।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक और बड़ी कार्रवाई, सरकारी योजनाओं का गलत लाभ उठाने का मामला

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी योजनाओं का गलत तरीके से लाभ उठाने के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। इस मामले में मुख्यमंत्री के निर्देश पर कोतवाली नगर और थाना राजपुर में दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। संबंधित अधिकारियों से कहा गया है कि ऐसे अपात्र लोगों को कतई बख्शा न जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए।

मामले में जिला पूर्ति अधिकारी देहरादून और आयुष्मान विभाग की ओर से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून को तहरीर दी गई। बताया गया कि सरकार की ओर से पांच लाख से कम सालाना आय वाले लोगों के राशन कार्ड बनाए जाते हैं। अपात्र लोगों की ओर से राशन कार्ड बनाए जाने की शिकायत मिलने पर पूर्ति विभाग ने राशन कार्डों की जांच की तो कई लोगों के राशन कार्ड फर्जी पाए गए।

पौड़ी जिला पंचायत में सफाई टेंडर के नाम पर 75 लाख का घोटाला

पौड़ी (नजरिया खबर ब्यूरो)। प्रदेश की राजधानी में देहरादून नगर निगम सफाई कर्मचारी घोटाला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि इसी तरह का घोटाला पौड़ी जिले से भी सामने आ गया है। घोटाले का खुलासा आरटीआई के जरिए हुआ है।

आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है कि 15 ब्लॉक में सफाई के नाम पर 75 लाख का घपला हुआ है। डीएम खुद इसकी जांच कर रही हैं। जिला पंचायत पौड़ी में सफाई टेंडर के नाम पर 75 लाख का घोटाला सामने आया है। इस घोटाले में साफ-सफाई कार्यों के नाम पर 75 लाख रुपये की सरकारी धनराशि एक उपनल कर्मचारी की पत्नी के खाते में स्थानांतरित की गई है। यह खुलासा सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई

जानकारी से हुआ है।

आरटीआई कार्यकर्ता करन रावत ने जून 2025 के पहले सप्ताह में आरटीआई के तहत जवाब प्राप्त किया।

करन रावत ने इस मामले की शिकायत गढ़वाल आयुक्त से की, जिसके बाद पत्रावली पौड़ी जिलाधिकारी कार्यालय को भेजी गई। उन्होंने मांग की है कि इस घोटाले की विजिलेंस जांच हो और दोषियों पर एफआईआर दर्ज हो। 2024-25 की ऑडिट रिपोर्ट में यह साफ हुआ कि हर ब्लॉक में औसतन दो सफाई कर्मचारी नियुक्त दिखाए गए, जिन्हें 15,000 रुपये मासिक और वीआईपी ड्यूटी व दुर्गम क्षेत्रों में तैनात 10 कर्मचारियों को 30 हजार रुपये तक तक मासिक भुगतान किया।

अनामिका राज और मणिका जोशी बने मिस टैलेंटेड

देहरादून (नजरिया खबर ब्यूरो)। सिनमिट कम्प्युनिकेशंस की ओर से सेंटरियो मॉल में मिस उत्तराखंड-2025 के सब कॉन्टेस्ट मिस टैलेंटेड और मिस बॉलीवुड का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रतिभागियों ने एक्टिंग, डांस और सिंगिंग कर अपना टैलेंट दिखाया। इस मौके पर अनामिका राज और मणिका जोशी मिस टैलेंटेड चुनी गईं।

सिनमिट कम्प्युनिकेशंस की ओर से हर वर्ष की तरह इस बार भी मिस उत्तराखंड-2025 का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर गुरुवार को न्यू कैंट रोड स्थित सेंटरियो मॉल में सब कॉन्टेस्ट आयोजित हुए। जिसमें देहरादून सहित, हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तरकाशी, नैनीताल, रुद्रपुर, पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर, खटीमा आदि जगहों की युवतियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने अपने हुनर



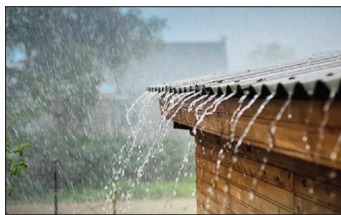
मिस टैलेंटेड अनामिका व मणिका।

का प्रदर्शन किया। इस मौके पर सिनमिट कम्प्युनिकेशंस के डायरेक्टर दलीप सिंधी ने बताया कि जुलाई माह में ही मिस उत्तराखंड के ग्रैंड फिनाले का आयोजन होगा। उन्होंने ये भी बताया कि पहली बार मिस उत्तराखंड की विनर को फेमिना मिस इंडिया उत्तराखंड में डायरेक्ट एंट्री मिल सकेगी। वही प्रतिभागी भी इसको लेकर बेहद उत्साहित है।

ग्रैंड फिनाले का आयोजन हयात सेंट्रिक में किया जाएगा। डायरेक्टर राजीव मित्तल ने बताया कि ये वाकई में हमारे लिए बेहद ही गौरव की बात होगी, जबकि यहां की विनर को फेमिना मिस इंडिया उत्तराखंड में डायरेक्ट एंट्री मिल सकेगी। वही प्रतिभागी भी इसको लेकर बेहद उत्साहित है।

उत्तराखंड में बारिश का कहर: इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट डेटा में भारी वर्षा की पुष्टि

देहरादून (नजरिया खबर ब्यूरो)। देहरादून स्थित पर्यावरणीय एक्शन और एडवोकेसी समूह सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्प्युनिटी फाउंडेशन ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय को पत्र भेज कर आगामी 24 और 28 जुलाई, 2025 को प्रस्तावित पंचायत चुनावों को स्थगित करने की अपील की है। यह अपील भारत मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों पर आधारित है जो राज्य में असामान्य रूप से तीव्र और अस्थिर मानसून की ओर इशारा कर रहे हैं जिससे जन-जीवन को गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है। मौसम विभाग देहरादून के अनुसार जून



सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्प्युनिटी फाउंडेशन ने पंचायत चुनाव टालने की लगाई हाईकोर्ट से गुहार

2025 में राज्य में 240 मिमी वर्षा दर्ज हुई, जबकि सामान्य आंकड़ा 176 मिमी होता है जो 36: की वृद्धि है। 25 जून से 2 जुलाई के बीच, औसतन 130.1 मिमी वर्षा हुई जो कि सामान्य

66.2 मिमी के मुकाबले 96: अधिक है। जुलाई वैसे भी उत्तराखंड का सबसे अधिक वर्षा वाला महीना होता है जिसमें औसतन 417 मिमी वर्षा होती है। ऐसे में यह संकेत है कि भूस्खलन, बाढ़, ढलानों का टूटना और व्यापक जन-विघटन की आशंका अत्यधिक बढ़ गई है। एसडीसी फाउंडेशन ने अपनी अपील में कहा है कि यह आंकड़े केवल सांख्यिकीय नहीं हैं, बल्कि यह प्राकृतिक आपदाओं और बढ़ते खतरों का सीधा संकेत हैं। 1 से 28 जून 2025 के बीच 65 लोगों की मौत वर्षा और आपदा से जुड़ी घटनाओं में हो चुकी है जो कि पिछले

साल की तुलना में 103: अधिक है। इसमें 29 जून को उत्तरकाशी में बादल फटने और फलैश फ्लड में दो लोगों की मौत और सात लोगों के लापता होने की घटना शामिल है। 26 जून को बद्रीनाथ हाईवे पर घोलतीर गांव के पास एक यात्री वाहन के अलकनंदा नदी में गिरने से छह लोगों की मृत्यु हो गई। 28 जून को अकेले भारी बारिश और भूस्खलन के कारण 160 से अधिक सड़कें बंद हो गईं जिससे कई स्थानों का संपर्क टूट गया।

एसडीसी फाउंडेशन के अनूप नौटियाल जो वर्षों से उत्तराखंड में जलवायु संकट, आपदा प्रबंधन और

नागरिक-नेतृत्व वाले पर्यावरणीय अभियानों पर काम कर रहे हैं ने कहा कि ऐसे हालात में पंचायत चुनाव कराना लाखों मतदाताओं को जान जोखिम में डालकर मतदान केंद्र तक लाने जैसा है जिनमें से कई को पैदल खतरनाक इलाकों से गुजरना होगा। साथ ही लगभग 80000 से एक लाख सरकारी कर्मियों की चुनावी ड्यूटी भी इन्हीं संवेदनशील इलाकों में लगाई जाएगी। जब मौसम विभाग बार-बार रेड और येलो अलर्ट जारी कर नागरिकों को घर में रहने की सलाह दे रहा है, ऐसे में चुनाव करवाना मानवीय संकट का कारण बन सकता है।

जनमन के हक पर डाका डालने वालों की प्रशासन ने मरोड़ी गर्दन, 3323 राशन कार्ड, 9428 आयुष्मान कार्ड निरस्त

देहरादून (नजरिया खबर ब्यूरो)। जिलाधिकारी सविन बंसल ने जिले में अपात्र राशन एवं आयुष्मान कार्ड पर की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए सत्यापन की कार्यवाही शुरू की गई जिसमें पाया कि 136676 निष्क्रिय राशन कार्डों से 9428 आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन ने 3323 राशन कार्ड तथा 9428 आयुष्मान कार्ड को निरस्त कर सम्बन्धितों के विरुद्ध नगर कोतवाली एवं थाना राजपुर रोड में मुकदमा दर्ज करवाया है। जांच जारी है, गलत अभिलेख प्रस्तुत कर राशन कार्ड बनाए जाने के फलस्वरूप कार्यवाही की गई है।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर, जिला प्रशासन का राशन व आयुष्मान कार्ड माफियाओं पर प्रहार जारी है। जनमन के हक पर डाका डालने वालों की प्रशासन ने गर्दन मरोड़ते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई है तथा 3323 राशन कार्ड, 9428 आयुष्मान कार्ड निरस्त, कर दिए गए हैं। ऐसा राज्य



जिलाधिकारी सविन बंसल निरीक्षण करते हुए।

के किसी जिले में प्रथमबार, राशनकार्ड व आयुष्मान कार्ड फर्जीवाड़े पर जिला प्रशासन सख्त एक्शन ले रहा है। जिला प्रशासन अपने कड़े व सख्त एक्शन से राशन व आयुष्मान कार्ड माफिया गिरोहों को कुचलने का कार्य कर रहा है। जांच में सामने आया कि राशन कार्ड बनवाने के लिए फर्जी अभिलेख दिए गए हैं जिस पर जिला प्रशासन ऐसे गिरोहों पर सख्त कार्यवाही का मन बना चुका है, जांच में यह भी सामने

आया कि निष्क्रिय 136676 राशन कार्डों से 9428 आयुष्मान कार्ड बने हैं।

जिला प्रशासन के राशन कार्ड सत्यापन के दौरान 3323 राशन कार्ड निरस्त किये गये हैं। निरस्त किये गये राशन कार्डों की मात्रा अधिक होने के कारण कुछ लोगों द्वारा गलत दस्तावेज प्रस्तुत कर राशन कार्ड बनवाये गए हैं। निरस्त किये गये कार्डों पर जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को विधिक कार्यवाही किये

जाने के निर्देश दिये गये थे जिसके क्रम में थाना कोतवाली नगर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 336(2) व धारा 336(3) के तहत सम्बन्धितों पर मुकदमें दर्ज किए गए हैं।

वहीं राज्य स्वास्थ्य प्रा० को जिला खादय आपूर्ति कार्यालय देहरादून द्वारा निरस्त किए गए राशन कार्ड 1,36,676 का डेटा प्रदान किया गया था। उक्त 136676 राशन कार्ड के सापेक्ष 9,428 आयुष्मान कार्ड बने हुए पाए गए हैं। जिनको एसएचए द्वारा निष्क्रिय करने की प्रक्रिया गतिमान है व 9428 कार्डों को निरस्त किये भी जा चुके हैं। उक्त आयुष्मान कार्डों को बनाए जाने में किसी गिरोह के होने की सम्भावना होने के फलस्वरूप लिहाजा सम्बन्धितों के विरुद्ध थाना राजपुर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। जनपद में कुल 387954 राशन कार्ड हैं जिनमें 75576 राशन कार्ड सत्यापित हैं 3323 राशन कार्ड निरस्त किए गए हैं।

माता रानी के विशाल भंडारे का आयोजन

देहरादून। माँ डाटकाली मनोकामना सिद्धपीठ के 222वें वार्षिकोत्सव के छठे दिन माता रानी के विशाल भंडारे का आयोजन किया गया।

प्रातः माता रानी के जागरण की भव्य प्रातः 6 बजे हुए, उसके बाद कन्य पूजन कर माता का हलवा चने का प्रसाद वितरित किया गया। प्रातः 9 बजे आषाढ़ शुक्ल पक्ष नवमी का हवन मंदिर प्रांगद में हुआ उपरांत माता रानी के पवित्र झण्डों का पूजन कर सांही मंदिर में स्थापित किए गये, प्रातः 11 बजे विशाल भंडारा प्रारंभ हुआ जो कि देर शाम तक भक्तों में वितरित होता रहा। माँ का पवित्र भंडारा खाकर भक्त निहाल होगये, सायकल माँ अन्नपूर्णा की आरती करके माँ का आभार व्यक्त किया। महंत रमन प्रसाद गोस्वामी जी ने वार्षिकोत्सव के विधि विधान से संपन्न होने पर सभी भक्तों को बधाई व आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर शुभम गोस्वामी, संयम गोस्वामी, दिनेश अग्रवाल, गौरव कुमार, शिवम् गोयल, नरसिंह दास, पंकज चंदना आदि मौजूद रहे।

एनसीडब्ल्यू व ईडीआईआई महिला उद्यमिता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने को एकजुट

देहरादून (नजरिया खबर ब्यूरो)। समावेशी विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (ईडीआईआई) और राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने मिलकर महिला उद्यमियों के साथ विजया के. रहाटकर, अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग का एक संवादात्मक सत्र का आयोजन किया।

यह कार्यक्रम का आयोजन ईडीआईआई परिसर में हुआ जहां श्रशिवानी डे, उप सचिव, एनसीडब्ल्यूय रामावतार सिंह, प्रमुख प्रशिक्षण, एनसीडब्ल्यू और डॉ. सुनील शुक्ला, डायरेक्टर जनरल, ईडीआईआई भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का एक मुख्य आकर्षण 'यशोदा एआई' पर

वर्कशॉप थी, जो एक डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम है जिसे विशेष रूप से महिलाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा की बुनियादी जानकारी देने के लिए डिजाइन किया गया है। विजया के. रहाटकर ने महिलाओं को नेतृत्व के अधिक अवसर देने, उन्हें व्यवसाय शुरू करने और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया के साथ तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता पर बात की। रहाटकर ने कहा, महिलाओं को सशक्त बनाना केवल उन्हें कौशल प्रदान करना नहीं है, बल्कि उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना और सोच को परिवर्तित करना भी है। महिलाएं स्वयं को सुरक्षित, सक्षम और नेतृत्व के लिए तैयार महसूस करें कृ चाहे वह व्यवसाय हो, तकनीक हो या दैनिक जीवन।

अस्पताल के दावों का यथा समय हो निस्तारण: स्वास्थ्य मंत्री

देहरादून (नजरिया खबर ब्यूरो)। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण: आयुष्मान योजना की समीक्षा बैठक में मा. स्वास्थ्य मंत्री डा धन सिंह रावत ने आयुष्मान योजना के सेवा प्रदाता अस्पतालों के दावों का यथा समय निस्तारण करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने पर्वतीय जनपदों में संचालित अस्पतालों को आयुष्मान के प्रति प्रोत्साहित करने के प्रयासों को भी जरूरी बताया।

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण में आयोजित समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डा धन सिंह रावत ने कहा कि आयुष्मान योजना आम जन मानस के जीवन से जुड़ी है। इसको बेहतर ढंग से संचालित करने हेतु सभी को बहुत गंभीरता से काम करना होगा। उन्होंने अस्पताल की ओर से आने वाले उपचार के दावों का यथा समय निस्तारण करने के निर्देश दिए। राज्य



स्वास्थ्य मंत्री बैठक लेते हुए।

एसजीएएस में बजट की समस्या के निस्तारण पर हुई चर्चा

सरकार स्वास्थ्य योजना में बजट की स्थितियां स्पष्ट करने हेतु मंत्री ने फिर से वित्त के अधिकारियों से संयुक्त बैठक के निर्देश दिए। उन्होंने परिवार रजिस्टर से आयुष्मान कार्ड बनाने की औपचारिता शीघ्र पूर्ण

करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा बैठक में आयुष्मान के संतुलित पैकेज मास्टर तैयार करने, पर्वतीय क्षेत्रों के अस्पतालों को प्रोत्साहित करने समेत कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस अवसर पर राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रीना जोशी, निदेशक वित्त अभिषेक आनंद आदि मौजूद रहे।

खनन विभाग ने राजस्व प्राप्ति में आज तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ स्थापित किये नये आयाम

देहरादून (नजरिया खबर ब्यूरो)। प्रदेश में खनन के क्षेत्र में किए गए सुधारों एवं अवैध खनन पर रोक लगाने के कारगर प्रयासों के फलस्वरूप खनन से राजस्व प्राप्ति के नित नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में खनन विभाग ने रु. 331.14 करोड़ का राजस्व अर्जित कर नया रिकॉर्ड कायम किया है, जो गत वर्ष की तुलना से 22.47 प्रतिशत अधिक है। गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी राज्य में खनन से राजस्व प्राप्ति के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ कुल रु. 1040.57 करोड़ राजस्व का अर्जन

गत वित्तीय वर्ष में भी रिकॉर्ड तोड़ कुल रु. 1040.57 करोड़ राजस्व का अर्जित हुआ था

किया गया था। राज्य में खनन के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम तिमाही में रु. 146.18 करोड़, वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रथम तिमाही में रु. 177.27 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रथम तिमाही में रु. 270.37 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था। जबकि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 की प्रथम तिमाही में खनन से रु. 331.14 करोड़ का राजस्व की प्राप्ति हुई है, जो विगत वर्ष की तुलना

से 22.47 प्रतिशत अधिक है तथा अन्य वर्षों की अपेक्षा कई गुना अधिक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश के विकास के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था हेतु राजस्व वृद्धि के उपायों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है। जिनके उल्लेखनीय परिणाम सामने आ रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा खनन से राजस्व वृद्धि के लिए उपखनिज परिहार नियमावली और उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली में सरलीकरण करने के साथ ही नये

खनिज लॉटो का चिन्हीकरण कर ई-निविदा सह-ई नीलामी के माध्यम से आवंटित करने की व्यवस्था की गई है। अवैध रूप से किए जाने वाले खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर प्रभावी रोकथाम के लिए खनन निदेशालय के स्तर पर गठित प्रवर्तन दलों के माध्यम से निरन्तर कार्रवाई करने के साथ ही जिला स्तर पर भी अवैध खनन रोकने के लिए त्वरित व प्रभावी कार्रवाई करने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य की आर्थिक मजबूती के लिए राजस्व प्राप्ति के संसाधनों में वृद्धि किया

जाना आवश्यक है। राज्य के हित में खनिज संसाधनों का समुचित और युक्तिसंगत तरीके से उपयोग करने पर ध्यान देने के साथ ही अवैध खनन पर सख्त नियंत्रण, पारदर्शी व्यवस्था, ठोस निगरानी और नियमों के सख्त अनुपालन पर जोर दिया गया है। आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर खनन प्रक्रियाओं को बेहतर बनाया गया है, जिससे खनिज संपदा का समुचित दोहन हो और राज्य की आय में बढ़ोतरी हो। इसके अलावा खनन उद्योग से जुड़े रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

फिल्म, कला और नीति निर्माण से जुड़े प्रमुख व्यक्तित्वों ने उत्तराखंड को रचनात्मकता और उद्यमिता का केंद्र बनाने पर विचार विमर्श किया

देहरादून (नजरिया खबर ब्यूरो)। मंथन — इमर्जिंग उत्तराखंड 2025 कार्यक्रम के दौरान होटल हयात रीजेंसी, देहरादून में आयोजित 'फिल्म इंडस्ट्री और अर्थव्यवस्था' विषयक पैनल चर्चा में प्रख्यात फिल्म निर्माता कुनाल शमशेर मल्ला ने अपने विचारों से सबको प्रभावित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ।

इस अवसर पर फिल्म, कला और नीति निर्माण से जुड़े प्रमुख व्यक्तित्वों ने उत्तराखंड को रचनात्मकता, विकास और उद्यमिता का केंद्र बनाने पर विचार-विमर्श किया। फिल्म जगत के चर्चित नामों कृ मुकेश तिवारी, विपुल मेहता और आरुषि निशंक कृ के साथ मंच साझा करते हुए कुनाल मल्ला ने कंटेंट-केंद्रित सिनेमा की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा, कहानी एक राजा की तरह होनी चाहिए। उन्होंने मेनस्ट्रीम फिल्मों में गिरते कंटेंट स्तर



को लेकर चिंता जताते हुए कहा, "आज जब फिल्म मार्केट में जाते हैं तो निर्माता और वितरक सबसे पहले पूछते हैं कि स्टार कौन है, न कि कहानी क्या है।

फिल्म का बजट नहीं, उसकी आत्मा उसे महान बनाती है।" गढ़वाली सिनेमा के प्रति अपने जुनून को साझा करते हुए कुनाल मल्ला ने कहा कि वे उस दिन की कल्पना करते हैं जब गढ़वाल की फिल्मों में भी तमिल, तेलुगु या मलयालम फिल्मों जैसी पहचान पाएंगी। उन्होंने

कहा, "हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा कृ हमारे घरों, आस-पास के माहौल और आम लोगों से जुड़ी कहानियों को फिर से खोजना होगा। मैं उस दिन का सपना देखता हूँ जब बॉलीवुड गढ़वाली फिल्मों से प्रेरित होगा, न कि गढ़वाली सिनेमा बॉलीवुड की।" इस सत्र का संचालन अभिषेक मैदोला ने किया, जिसमें फिल्म और मीडिया जगत से जुड़े कई दिग्गजों ने भाग लिया और उत्तराखंड में फिल्म नीति, प्रशिक्षण ढांचा और सिनेमा के आर्थिक प्रभाव जैसे विषयों पर सार्थक

चर्चा हुई। कुनाल शमशेर मल्ला देहरादून निवासी अभिनेता, निर्देशक, निर्माता, शिक्षाविद और मार्शल आर्ट विशेषज्ञ हैं। वे ओलंपस हाई स्कूल के संस्थापक और उत्तराखंड स्टेट ऑडिट बोर्ड के सदस्य हैं। उन्होंने 40 वर्ष की उम्र में अभिनय की दुनिया में कदम रखा और से यस टू लव, माजी, दम लगाके हईशा जैसी फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा वे देव भूमि जैसी अंतरराष्ट्रीय फिल्मों का भी हिस्सा रहे हैं। अभिनय के साथ-साथ वे एक प्रशिक्षित गायक, ब्लैक बेल्ट मार्शल आर्टिस्ट और क्षेत्रीय सिनेमा एवं संस्कृति के सशक्त समर्थक भी हैं। उनकी आने वाली फीचर फिल्म 5 सप्टेंबर, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब तक 40 से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं, जल्द ही रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में संजय मिश्रा, अतुल श्रीवास्तव, विक्टर बनर्जी, कविन दवे, सरिका सिंह दवे, किरण दुबे और मानिनी मिश्रा जैसे दमदार कलाकार नजर आएंगे।

मलतूरा के पास वाहन दुर्घटनाग्रस्त में चालक हुआ घायल

चमोली। कर्णप्रयाग—गवालदम राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलतूरा के ऋपास टाटा सूमो गहरी खाई में गिरने से चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे थाना थराली पुलिस ने रेस्क्यू कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली में भर्ती किया।

कोतवाली थराली पंकज कुमार ने बताया सड़क से करीब 25 मीटर नीचे गहरी खाई में गिरा वाहन संख्या यू के 02 टी ए 1429 को चेक किया गया तो चालक नवीन चंद्रपुत्र मोहन राम निवासी ग्राम दुधीला पोस्ट ऑफिस घेठा थाना कौसानी जिला बागेश्वर उम्र 42 वर्ष घायल अवस्था में मिला। जिसे स्ट्रेचर पर बांधकर पुलिस बल तथा ग्रामीणों की मदद से सड़क पर लाया गया। चालक के द्वारा बताया गया कि रात्रि में वह वाहन में अकेला ही कर्णप्रयाग से बागेश्वर की तरफ जा रहा था। रात्री समय करीब 9रु30 बजे गाड़ी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। घायल चालक को थराली अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों की मौजूदगी में किया ईवीएम वेयर हाउस का मासिक निरीक्षण



चमोली (नजरिया खबर ब्यूरो)। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप तिवारी ने शनिवार को राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की मौजूदगी में ईवीएम वेयर हाउस का मासिक निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान ईवीएम व वीवीपैट मशीनें डबल लॉक में सुरक्षित पाई गई। जिलाधिकारी ने वेयर हाउस

में विद्युत व्यवस्था, सीसीटीवी कंट्रोल रूम, साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया।

इस मौके पर सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी सती, कांग्रेस पार्टी के मदन लोहानी, आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष अनूप सिंह रावत सहित अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे।

जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री घोषणाओं के कार्यों की समीक्षा की

चमोली (नजरिया खबर ब्यूरो)। जिलाधिकारी संदीप तिवारी की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री घोषणाओं से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री घोषणाओं की विभागवार समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री घोषणा के कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने और कार्यों की नियमित रिपोर्ट उपलब्ध कराने के आदेश दिए। साथ ही उन्होंने जिला स्तर पर लम्बित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित कर योजनाओं का कार्य शुरू करवाने की बात कही। वहीं उन्होंने शासन स्तर पर लम्बित प्रकरणों का फॉलोअप कर योजनाओं की प्रगति की जानकारी देने के निर्देश



दिए। जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में योजनाओं का निर्माण पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा मुख्यमंत्री घोषणाएं सीधेतौर पर आम जनता के हितों से जुड़ी होती है। ऐसे में अधिकारी घोषणाओं के क्रियान्वयन को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र करवाना सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने लोनिवि के अधिकारियों को तहसील प्रशासन और वन विभाग से

समंवय स्थापित कर भूमि से सम्बन्धित मामलों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अतिरिक्त धन की आवश्यकता वाली योजनाओं के पुनः प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध कराने की बात कही। बैठक में बताया गया कि वर्तमान तक जनपद के लिए माननीय मुख्यमंत्री की ओर से कुल 150 योजनाओं की घोषणा की गई हैं। जिनमें से 40 घोषणाएं पूर्ण, 42 प्रगतिरत, 50 शासन स्तर तथा 18 घोषणाएं जिला स्तर पर लंबित हैं।

बरसात के सीजन में निर्बाध चुनाव कराने में जुटा राज्य चुनाव आयोग व आपदा प्रबन्धन विभाग

देहरादून (नजरिया खबर ब्यूरो)। उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में आपदा जैसी स्थिति बन गई है। जबकि, इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश होने की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। इसी बीच 24 और 28 जुलाई को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर वोटिंग भी होनी है। उस दौरान भारी बारिश और पर्वतीय क्षेत्रों में बनी आपदा की स्थिति एक बड़ी चुनौती बन सकती है।

बारिश को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग और आपदा प्रबंधन विभाग ने चुनाव को लेकर रणनीतियां बनानी शुरू कर दी है। ताकि, बिना

प्राकृतिक व्यवधान के चुनाव कराया जा सके। आखिर क्या है राज्य निर्वाचन आयोग और आपदा प्रबंधन विभाग की रणनीति? हर साल मानसून सीजन के दौरान भारी बारिश के चलते आपदा जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से लगातार हुई भारी बारिश के चलते आपदा की स्थिति बन गई है। इतना ही नहीं भारी बारिश के चलते होने वाले भूस्खलन की वजह से तमाम रास्ते बाधित हो गए हैं। यही वजह है कि आने वाले दिनों में प्रदेश में भारी बारिश के चलते आपदा जैसी स्थिति

बनने की भी संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने फिलहाल 7 जुलाई तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही इस जुलाई महीने में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की भी संभावना जताई है। इसी महीने पंचायत चुनाव हो रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से 28 जून को जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार 24 और 28 जुलाई को मतदान होना है। साथ ही 31 जुलाई को मतगणना होनी है। वर्तमान समय में प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बनी स्थितियों के चुनाव करना

शासन-प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। राज्य निर्वाचन आयोग भी इस बात को मान रहा है कि मानसून में चुनाव कराना चुनौती है। जिसके चलते सभी जिलाधिकारियों और आपदा प्रबंधन को व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। ताकि, सामान्य दिनों की तरह ही चुनाव को संपन्न कराया जा सके। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने अहम जानकारी दी। राज्य निर्वाचन आयोग सुशील कुमार ने कहा कि इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मानसून के दौरान हो रहा है।

जिसका शुरू से ही इसका विशेष ध्यान रखा गया है। ऐसे में संभावित परिस्थितियों को देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को कहा गया है कि आपदा को देखते हुए चुनाव के लिए कंटीजेंसी प्लान बनाएं। ताकि, चुनाव के दौरान बारिश या मार्ग बाधित होती है तो उस दौरान पोलिंग पार्टियों और मतदाताओं का आवागमन बाधित न हो। साथ ही मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद पोलिंग पार्टियां सुरक्षित अपने गंतव्य पर पहुंच जाए। उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से बारिश के दौरान होने वाले सड़कों के अवरुद्ध को देखना है।

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने मोबिलिटी प्लान से संबंधित एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण की बैठक ली

देहरादून (नजरिया खबर ब्यूरो)। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने शुक्रवार को सचिवालय में देहरादून शहर के मोबिलिटी प्लान से सम्बन्धित एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण की बैठक ली। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने देहरादून शहर के लिए यातायात संकुलन योजना की प्रगति की जानकारी ली।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को मोबिलिटी प्लान के तहत सुधारीकरण के लिए चिन्हित 10 स्थानों में सुधार प्रक्रिया में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन सुधारीकरण कार्यों की डीपीआर तैयार हो चुकी है अगले एक माह में कार्य शुरू कराए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बाकी कार्यों की डीपीआर भी 31 जुलाई तक तैयार किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिलाधिकारी को लगातार इसकी मॉनिटरिंग किए जाने के निर्देश दिए हैं ताकि कार्यों को समय से पूर्ण किया जा सके। मुख्य सचिव ने कहा कि जिन सड़कों



मुख्य सचिव बैठक लेते हुए।

का अभी चौड़ीकरण किया गया है, उन सड़कों में नो पार्किंग जोन होते हुए वाहनों के खड़े होने से पूर्व जैसी ही स्थिति बनी हुयी है। उन्होंने कहा कि नो पार्किंग जोन में वाहन खड़े न हों इसके लिए प्रभावी प्रवर्तन कराया जाए। उन्होंने कहा कि इस समस्या के लिए लगातार नए पार्किंग स्थलों के तलाशे जाने की प्रक्रिया लगातार जारी रखी जाए। उन्होंने कहा कि कमर्शियल भवनों की पार्किंग को 100 प्रतिशत प्रयोग किए जाने हेतु

लगातार कार्य कराए जाएं। उन्होंने सचिवालय, पवेलियन ग्राउण्ड और परेड ग्राउण्ड के नीचे अंडरग्राउण्ड पार्किंग की सम्भावनाओं को तलाशे जाने के भी निर्देश दिए हैं। सीएमपी में चिन्हित सम्भावित पार्किंग स्थलों को एक्सप्लोर किया जाए।

मुख्य सचिव ने आदृत बाजार शिपिंग प्रक्रिया में तेजी लायी जाए। उन्होंने भूमि आबंटन की प्रक्रिया में देरी पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आदृत बाजार शिपिंग के कार्य में

विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए टाईमलाइन निर्धारित की जाए एवं मुख्य सचिव कार्यालय को शीघ्र अवगत कराया जाए। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग भी मोबिलिटी प्लान के अनुरूप एसपीवी के गठन की कार्यवाही में तेजी लाते हुए अगले 15 दिनों के प्रस्ताव कैबिनेट में लाए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने देहरादून के लिए अगले 25-30 सालों की यातायात संकुलन की समस्या को देखते हुए योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए शीघ्र ही बैठक आयोजित की जाए। इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल, अपर सचिव विजय कुमार जोगदंडे, रीना जोशी, पूजा गर्ब्याल एवं उत्तराखण्ड मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से बृजेश कुमार मिश्रा सहित सम्बन्धित विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

लाखन मंडी ग्राम सभा क्षेत्र से ज्योति दीपक चौसाली का एकमात्र नामांकन होने से उनका निर्विरोध प्रधान बनना तय

लालकुआं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन के आज अंतिम दिन चोरगलियां क्षेत्र के लाखन मंडी ग्राम सभा से एकमात्र ज्योति दीपक चौसाली का ग्राम प्रधान के लिए नामांकन होने के बाद ज्योति दीपक चौसाली का निर्विरोध ग्राम प्रधान बनना तय हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन था, अंतिम दिन तक चोरगलियां के लाखन मंडी ग्राम सभा क्षेत्र से ग्राम प्रधान पद के लिए एकमात्र ज्योति दीपक चौसाली का नामांकन होने के चलते ज्योति दीपक चौसाली का निर्विरोध ग्राम प्रधान बनना तय हो गया है, क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने ज्योति दीपक चौसाली को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।



नदी उत्सव कार्यक्रम में नदियों की निर्मलता और स्वच्छता का लिया संकल्प

हरिद्वार (नजरिया खबर ब्यूरो)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के मुख्य सेवक के रूप में अपने सफल चार वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड में मां गंगा की विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रदेश की समृद्धि, शांति और प्रगति की कामना की।

मुख्यमंत्री ने नदी उत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नदियां केवल जल स्रोत नहीं, बल्कि प्राचीन काल से ही सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन की आधारशिला रही हैं। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए भी नदियों का संरक्षण और संवर्धन अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे नदियों

का 'मां' के समान सम्मान करें और उन्हें स्वच्छ एवं निर्मल बनाए रखने में सहयोग करें। इस अवसर पर स्वयं मुख्यमंत्री सहित उपस्थित श्रद्धालुओं ने नदियों को प्रदूषित न करने और उन्हें सदैव स्वच्छ बनाए रखने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में श्री गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम, सभापति कृष्ण कुमार शर्मा, स्वागत मंत्री सिद्धार्थ चक्रपाणि एवं अन्य पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक', राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी, विधायक मदन कौशिक, आदेश चौहान, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनय रुहेला, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, श्रद्धालु एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

हरिद्वार (नजरिया खबर ब्यूरो)।

उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड में कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले होटल-ढाबों की जांच को जा रहे स्वामी यशवीर महाराज को पुलिस ने बीच रास्ते में रोक लिया। अपने होटल नाम सत्यापन अभियान के तहत स्वामी यशवीर महाराज शुक्रवार को हरिद्वार के लिए रवाना हुए थे। लेकिन उत्तराखंड पुलिस ने उन्हें यूपी-उत्तराखंड बॉर्डर पर नारसन क्षेत्र में ही रोक दिया।

फिलहाल उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी गई है। मामले को लेकर स्वामी यशवीर महाराज के समर्थक भी मौके पर जुटने लगे हैं। स्थिति पर स्थानीय प्रशासन निगरानी बनाए हुए है। बता दें कि ये वही स्वामी यशवीर हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में पंडित जी वैष्णो ढाबा पर करने पहुंचे थे। इस



स्वामी यशवीर महाराज।

दौरान उनकी टीम ने जोरदार हंगामा किया। ढाबे के एक कर्मचारी ने आरोप लगाया कि स्वामी की टीम उसका पेंट उतारने की कोशिश कर रही थी। हालांकि स्वामी ने कर्मचारी के आरोप को बेबुनियाद बताया है। इस मामले में पुलिस ने स्वामी की टीम को नोटिस भी जारी किया है।

बता दें कि यूपी-उत्तराखंड की सरकार ने कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले होटलो, ढाबों, रेस्टोरेंट व रेहड़ी वालों

के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। पहला नियम यह है कि सभी को खाद्य विभाग से लाइसेंस लेना होगा।

दूसरा जिस नाम से लाइसेंस होगा, उसको दुकान के बाहर लगाना होगा। तीसरा नियम यह है कि सभी को अपने असली नाम का बोर्ड लगाना होगा। कावड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही एक बार फिर से दुकानों पर दुकानदार का नाम लिखने की बात उठने लगी है।

महंत इन्दिरेश अस्पताल के निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में उमड़े सहस्रपुरवासी, निशुल्क दवाईयां बांटीं

देहरादून (नजरिया खबर ब्यूरो)। श्री गुरु राम राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड हेल्थ साइंसेज एवम् श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल के कम्प्युनिटी मेडिसिन विभाग के 'फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम' के अन्तर्गत आज सहस्रपुर, देहरादून में एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया।

यह स्वास्थ्य शिविर जंगलात रोड, सहस्रपुर स्थित अनीस अहमद प्रधान के घर पर आयोजित किया गया। इस स्वास्थ्य शिविर में श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल के मेडिसिन विभाग के डॉ० अनमोल गोयल व डॉ. दीपा,



नेत्र परीक्षण करते चिकित्सक।

स्त्री एवम् प्रसूति रोग विभाग की डॉ० राशि वार्ष्णेय, सर्जरी विभाग के डॉ. उपमन्यु जोशी एवम् शिशु व बाल

रोग विभाग के डॉ० मोहम्मद शाबान व नेत्र रोग विभाग के डॉ. राजेश्वर सिंह एवम् डॉ. सुमित ओली ने रोगियों को चिकित्सकीय परामर्श दिए। शिविर में श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल की ओर से रोगियों की निःशुल्क ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर व नेत्र जाँचें भी की गईं।

शिविर में श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल की ओर से निःशुल्क दवाईयां भी वितरित की गईं। इस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का सहस्रपुर व इस क्षेत्र के ग्रामों ढाकी, रैदापुर चारबा, कुशालपुर, लक्ष्मीपुर चांचक व शंकरपुर आदि के 185 (एक सौ

पचासी) रोगियों ने लाभ उठाया। आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण रोगियों ने बढ़चढ़ कर शिविर का लाभ उठाया। इस अवसर पर श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल से जुड़े श्री गुरु राम राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड हेल्थ साइंसेज कम्प्युनिटी मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ० पुनीत ओहरी ने अपने सम्बोधन में कहा कि यह शिविर श्री गुरु राम राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड हेल्थ साइंसेज के कम्प्युनिटी मेडिसिन विभाग द्वारा राष्ट्रीय मेडिकल काउंसिल (एन०एम०सी०) के दिशा-निर्देशों पर 'फैमिली एडॉप्शन

प्रोग्राम' के अन्तर्गत किया जा रहा है। इस 'फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम' का उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर गरीब वर्ग को उन्हीं के क्षेत्र में निःशुल्क गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध करवाना है। डॉ० पुनीत ओहरी ने कहा कि एसजीआरआरआईएमएण्डएचएस का कम्प्युनिटी मेडिसिन विभाग समाज के आर्थिक रूप से कमजोर गरीब वर्ग की सेवा के मानवीय लक्ष्य के प्रति कृत संकल्पबद्ध है। जहां न्यूनतम मूल्य पर गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएँ विशेषज्ञ डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों की देख-रेख में उपलब्ध हैं।

मुख्य सचिव ने आमजन की समस्याओं को सुनने एवं उनके निराकरण पर विशेष ध्यान देने के लिए निर्देश

देहरादून (नजरिया खबर ब्यूरो)। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने शुक्रवार को सचिवालय में जिलाधिकारियों के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न मुद्दों की समीक्षा करते हुए दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को आमजन की समस्याओं को सुनने एवं उनके निराकरण पर विशेष ध्यान दिए जाने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग, पेयजल विभाग एवं अन्य ऐसे विभाग जो नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, अपने कार्यक्षेत्रों का दौरा अवश्य करें। उन्होंने विभागों को निर्देश दिए हैं कि टेढ़े हो चुके बिजली के खम्बों, लटकी तारों सहित टूटी पेयजल पाईपलाईनों की मरम्मत का कार्य तत्काल कराए जाएं। उन्होंने कहा कि जब तक अधिकारी फील्ड पर नहीं उतरेंगे, आमजन की समस्याओं से अवगत नहीं होंगे। उन्होंने सभी अधिकारियों को फील्ड का दौरा



मुख्य सचिव बैठक लेते हुए।

नियमित रूप से किए जाने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव ने सभी जनपदों में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) रजिस्ट्रेशन की प्रगति की भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि आमजन अधिक से अधिक संख्या में अपने विवाह का पंजीकरण कराएं इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाएं। उन्होंने कहा कि पंजीकरण के लम्बित मामलों को

तेजी से निस्तारित किया जाए। उन्होंने मैदानी जनपदों में पंजीकरण के लिए विशेष अभियान संचालित किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रायः देखा जा रहा है कि ऐसे विवाह पंजीकरण, जिनमें विवाह के समय पति-पत्नी दोनों या दोनों में से कोई एक नाबालिग रहा हो, परन्तु वर्तमान में पंजीकरण के समय दोनों बालिग हो चुके हैं, को अस्वीकार किया जा रहा

है, जो कि गलत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे विवाह के मामलों का भी पंजीकरण किया जाए। मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) की जिलावार समीक्षा करते हुए प्रत्येक जनपद से प्रत्येक केन्द्र की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने ब्लॉक स्तर पर 'ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों' की स्थापना के कार्य में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए। कहा कि जिन इकाइयों में निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है, उन इकाइयों में उपकरणों की व्यवस्था शीघ्र सुनिश्चित करते हुए ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों को सक्रिय किया जाए। इस अवसर पर सचिव शैलेश बगौली, चंद्रेश कुमार यादव, विनोद कुमार सुमन, अपर सचिव रंजना राजगुरु, विजय कुमार जोगदंडे, मनुज गोयल, अपर सचिव गृह निवेदिता कुकरेती सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

रविवार को उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट

देहरादून। उत्तराखंड के लिए रविवार समेत 9 जुलाई तक का मौसम का अलर्ट जारी कर दिया है। रविवार को पूरे प्रदेश में बारिश होगी। जो अलर्ट जारी किया गया है। उसके अनुसार गढ़वाल मंडल के 3 और कुमाऊं मंडल के एक जिले में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान लगाया गया है।

मौसम विभाग ने जिन जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, उनमें गढ़वाल मंडल के 3 जिले देहरादून, रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल हैं। कुमाऊं मंडल के जिस जिले में भारी से बहुत भारी बारिश होगी वो बागेश्वर है। इन जिलों में गर्जना के साथ बिजली भी चमकेगी। यहां बारिश का तीव्र से अति तीव्र दौर चलेगा। उत्तराखंड के शेष 9 जिलों में भी बारिश होगी। इन जिलों में गर्जन के साथ बिजली चमकेगी और बारिश के तेज दौर चलेंगे। इसके साथ ही मौसम विभाग ने 7, 8 और 9 जुलाई के लिए भी मौसम का अलर्ट जारी कर दिया है। 7 जुलाई को भी 6 जुलाई जैसा ही मौसम का पैटर्न रहेगा।

केंद्र सरकार ने कैम्पा की प्रस्तावित 439.50 करोड़ की कार्ययोजना को दी मंजूरी

देहरादून (नजरिया खबर ब्यूरो)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैम्पा की कार्यकारी समिति की बैठक में उत्तराखण्ड राज्य की रुपये 439.50 करोड़ की कार्य योजना को शत प्रतिशत मंजूरी दिये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री का आभार व्यक्त किया।

राष्ट्रीय कैम्पा की कार्यकारी समिति की बैठक में उत्तराखंड के अवशेष प्रस्तावों पर विचार किया गया तथा सभी को स्वीकृति प्रदान की गई। कैम्पा की राष्ट्रीय समिति ने पाया कि उत्तराखंड के द्वारा प्रस्तावित सभी कार्य मानकों के अनुरूप थे तथा उनसे संबंधित समस्त अपेक्षित विवरण भी समिति के समक्ष स्पष्टता से प्रस्तुत

किया गया। इस प्रकार इस वर्ष राज्य हित में कैम्पा के अंतर्गत एक बड़ी धनराशि विभिन्न कार्यों के लिए समय से उपलब्ध हो सकेगी। उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. समीर सिन्हा ने बैठक में प्रतिभाग कर अवगत कराया कि यह प्रथम अवसर है जब राज्य द्वारा प्रस्तावित वार्षिक योजना को पूरी तरह स्वीकृति मिली है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2025-26 के लिए उत्तराखंड राज्य कैम्पा की मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित संचालन समिति ने 439.50 करोड़ रुपये की कार्य योजना अनुमोदित कर भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित की थी। प्रथम चरण में इसके सापेक्ष भारत सरकार द्वारा 235.30 करोड़ रुपये की धनराशि की स्वीकृति मई 2025 में जारी की गई थी।

एक ही मंच पर 117 विभिन्न कंपनियों, संस्थानों ने किया संवाद

देहरादून (नजरिया खबर ब्यूरो)। देहरादून में मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन (नॉर्डन रीजन) कार्यक्रम के अंतर्गत विश्वभर से आई 117 विभिन्न कंपनियों, संस्थानों और राज्यों के प्रतिनिधियों के बीच विचार विमर्श हुआ। इस दौरान विभिन्न राज्यों और कंपनियों के बीच आपसी सहयोग और समन्वय से नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने को लेकर सहमति बनी।

वही विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप राज्यों में सिविल एविएशन की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। इस सत्र के दौरान हेलीपोर्ट के विस्तार, हेलीकॉप्टर के सदुपयोग, हवाई सेवाओं को सुगम और सुरक्षित बनाने पर भी चर्चा हुई। प्रतिनिधियों द्वारा हाल ही में हुई कुछ हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए इन हवाई यात्राओं को और



कॉन्फ्रेंस में प्रतिभाग करते हुए।

सुरक्षित बनाए जाने पर जोर दिया गया। विभिन्न कंपनियों द्वारा राज्यों के प्रतिनिधियों से संबंधित राज्यों में उड़ान सेवाओं के विस्तार के लिए विशेष नीति और सब्सिडी देने का भी आग्रह किया गया। पैनल डिस्कशन के दौरान हेली सेवाओं और ड्रोन सेवाओं के माध्यम से सड़क विहीन क्षेत्रों में भी हेली सेवाओं के विस्तार पर चर्चा हुई।

प्रतिनिधियों का कहना था कि हवाई सेवा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में बेहद सहायक सिद्ध हो रही है। जिससे जनहानि को न्यूनतम किया जा सकता है। चर्चा के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि राज्यों में स्थायी हेलीपैड्स की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस को भी अपनाना चाहिए।

स्वास्थ्य संवाद एवं चिकित्सा सेवा सम्मान समारोह में 26 उत्कृष्ट चिकित्सकों को किया गया सम्मानित

देहरादून (नजरिया खबर ब्यूरो)। विचार एक नई सोच सामाजिक संगठन व उत्तराखंड श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के संयुक्त तत्वावधान में राजधानी देहरादून में स्वास्थ्य संवाद एवं चिकित्सा सेवा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम देहरादून के सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी ऑडोटीोरियम में किया गया।

कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री, सड़क परिवहन अजय टम्टा, अति विशिष्ट अतिथि कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार, सुबोध उनियाल, विशिष्ट अतिथि

सेवा और संवेदना से बनता है सच्चा चिकित्सक: अजय टम्टा

अध्यक्ष राज्य महिला आयोग, कुसुम कंडवाल, अपर सचिव मुख्यमंत्री एवं महानिदेशक, सूचना बंशीधर तिवारी, निदेशक, चिकित्सा शिक्षा आशुतोष सयाना ने शिरकत की। स्वास्थ्य संवाद एवं चिकित्सा सेवा सम्मान समारोह-2025 में 26 उत्कृष्ट चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। स्वास्थ्य संवाद एवं चिकित्सा सेवा सम्मान समारोह-2025 कार्यक्रम राज्यभर में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले चिकित्सकों को सम्मानित

करने एवं चिकित्सा क्षेत्र में संवाद को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों से आए 31 समर्पित और प्रतिष्ठित चिकित्सकों को उनके अनुकरणीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर चिकित्सा, पत्रकारिता, साहित्य और तकनीकी के क्षेत्र में भी नवाचार और उपलब्धियों का मंचन हुआ। मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री, सड़क परिवहन अजय टम्टा ने कहा डॉक्टर समाज का मेरुदंड हैं। कोरोना काल हो या दुर्गम क्षेत्रों में सेवा, हमारे चिकित्सकों ने जो योगदान दिया है

वह अभूतपूर्व है। उत्तराखंड जैसे राज्य में, जहां भौगोलिक चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, वहां स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म, ई-हॉस्पिटल मैनेजमेंट, और टेलीमेडिसिन जैसी पहलों की अत्यधिक आवश्यकता है और इसके क्रियान्वयन में डॉक्टरों की भागीदारी बहुत अहम है। मैं इस मंच के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि अब समय आ गया है जब चिकित्सा सेवाओं को सिर्फ दया और करुणा नहीं, प्रबंधन और नवाचार के चश्मे से भी देखा जाना चाहिए। ऐसे आयोजन, जो सेवा और समर्पण को सार्वजनिक रूप से

पहचान देते हैं, दरअसल एक नई संस्कृति की शुरुआत करते हैं जहाँ सेवा देने वाले को 'सम्मान' ही नहीं, एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मैं सभी सम्मानित चिकित्सकों को शुभकामनाएं देता हूँ और आयोजकों को साधुवाद देता हूँ जिन्होंने इस मंच के माध्यम से समाज के मौन नायकों को सामने लाने का कार्य किया।

अति विशिष्ट अतिथि कैबिनेट मंत्री, उत्तराखंड सरकार सुबोध उनियाल ने कहा चिकित्सक न केवल एक पेशेवर हैं, बल्कि वे समाज के लिए एक प्रेरक शक्ति भी हैं।

धामी राज में एक के बाद एक दूटे कई सियासी मिथक

देहरादून (नजरिया खबर ब्यूरो)। जब से पुष्कर सिंह धामी उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री बने हैं तब से प्रदेश में एक के बाद एक कई सियासी मिथक दूटे हैं। किसी पार्टी की लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी से लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पद पर किसी व्यक्ति का रिपीट होना, ये सब पहली बार हुआ है।

धामी सरकार की तमाम उपलब्धियों को देखते हुए भाजपा हाईकमान ने सोच समझकर महेन्द्र भट्ट को दोबारा संगठन की कमान सौंपी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फ्री हैंड दिया गया है। यह तय हो चुका है कि मिशन-2027 की फतह का दारोमदार धामी-भट्ट की जोड़ी पर ही रहेगा। महेन्द्र भट्ट को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद पर बहाल करने से न केवल पार्टी में उनका कद बढ़ा है, बल्कि इससे प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी



जनहित में लिये गए फैसलों से मुख्यमंत्री धामी पर बढ़ता चला गया बीजेपी हाईकमान का भरोसा

की स्थिति भी अजेय हो गई है। संदेश साफ है कि भाजपा ने धामी के चेहरे पर 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। यूं तो प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के कई नेता दावेदारी कर रहे थे, हाईकमान को भी फैसला लेने में मुश्किलें हो रही थीं लेकिन महेन्द्र भट्ट को मुख्यमंत्री

धामी का खुला समर्थन हासिल था, जिससे पलड़ा उनके पक्ष में झुक गया। पार्टी सूत्रों का कहना है कि दून से लेकर दिल्ली तक पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता प्रदेश अध्यक्ष पद के लॉबिंग करने में जुटे थे, लेकिन धामी के समर्थन को देखते हुए पार्टी हाईकमान ने भट्ट के नाम पर अपनी मुहर लगा दी। दरअसल, मुख्यमंत्री धामी और भट्ट कैमिस्ट्री अभूतपूर्व है, यही वजह रही कि पिछले कुछ सालों में सरकार और संगठन के बीच जबरदस्त तालमेल देखने को मिला। कभी कोई ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई कि पार्टी को असहज होना पड़ा हो। वास्तविकता यह भी है कि उत्तराखण्ड ने पिछले 24 वर्षों में 10 मुख्यमंत्री देखे हैं। राजनैतिक अस्थिरता प्रदेश की पहचान रही है। एनडी तिवारी को छोड़कर कोई भी मुख्यमंत्री अपना पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर

पाया है। भाजपा के तो किसी भी मुख्यमंत्री को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। चूंकि भाजपा को प्रदेश की जनता लगातार दो बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता सौंप चुकी है लिहाजा अब भाजपा पर नैतिक दबाव भी है कि पुष्कर सिंह धामी अपना पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करें ताकि जनता के बीच सरकार की स्थिरता को लेकर एक अच्छा संदेश जाए। यह बात भी किसी से छिपी नहीं है कि भाजपा युवा नेता पुष्कर सिंह धामी को अपना 'लक्की चार्म' मानती है। धामी ही हैं जिन्होंने भाजपा को लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटाकर पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था। वह अपना विधानसभा का चुनाव हारकर भी बाजीगर बने थे। अब समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन, दंगा-रोधी कानून बनाने, लव, लैंड और थूक जिहाद के खिलाफ कार्रवाई

के उनके फैसलों ने उन्हें काफी लोकप्रिय बना दिया है और पार्टी देश के विभिन्न हिस्सों में हिंदू मतदाताओं को लुभाने के लिए उनकी छवि का इस्तेमाल करने लगी है। इधर, महेन्द्र भट्ट अपनी सादगी और मृदु व्यवहार की बदौलत गढ़वाल क्षेत्र से प्रभावशाली ब्राह्मण चेहरा बनकर उभरे हैं। बेबाक बयानों से उन्होंने 'हाईकोर हिन्दुत्व' की राह अपनाई है। धामी कुमाऊं से है और राजपूत हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों में फिट बैठता है। यही तमाम वजहें रहीं कि महेन्द्र भट्ट को लगातार दूसरी बार प्रदेश संगठन का मुखिया बनाया गया है। संदेश साफ है धामी-भट्ट की जोड़ी पर भाजपा हाईकमान को पूरा भरोसा है। अब निगेटिव नैरेटिव सेट करने वालों के लिए कोई स्पेश बाकी नहीं रह गया है।

देहरादून-बद्रीनाथ हाईवे पर जियो नेटवर्क सबसे मजबूत: ट्राई

देहरादून (नजरिया खबर ब्यूरो)। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा कराए गए स्वतंत्र ड्राइव टेस्ट (आईडीटी) परिणामों के अनुसार रिलायंस जियो नेटवर्क ने देहरादून-बद्रीनाथ हाईवे पर शानदार प्रदर्शन किया है।

देहरादून-बद्रीनाथ हाईवे का अधिकतर हिस्सा, उत्तराखंड में चल रही चार धाम यात्रा मार्ग में शामिल है। इस हाईवे पर 325 किलोमीटर में 5 मई से 21 मई, 2025 के बीच ड्राइव-टेस्ट किया गया। जिसमें कॉल कनेक्ट रेट, डेटा डाउनलोड स्पीड, कॉल ड्रॉप रेट जैसे सभी मानदंडों पर जियो अव्वल रहा। देहरादून से बद्रीनाथ राजमार्ग के

साथ मुरादाबाद शहर को भी टेस्ट में शामिल किया गया था, दूरसंचार के नजरिए से दोनों क्षेत्र यूपी पश्चिम सर्किल का हिस्सा हैं। जियो नेटवर्क पर कॉल कनेक्ट होने की सफलता दर 98.77 फीसदी रही। यानी जितनी भी कॉल जियो नेटवर्क पर लगाई गई, उनमें से 98.77: कॉल कनेक्ट हो गई। एयरटेल की कॉल कनेक्ट होने की सफलता 96.34: तो वोडाफोन आइडिया की 92.93 प्रतिशत रही। बीएसएनएल 78.44: के साथ चौथे नंबर पर रही। ट्राई द्वारा रियल टाइम में किए गए ड्राइव टेस्ट के मुताबिक, जियो ने कॉल सेटअप में लगने वाले टाइम के मामले में भी अच्छा प्रदर्शन किया है।

नैनीताल पुलिस का नए कानूनों के प्रति जागरूकता अभियान

नैनीताल। पुलिस मुख्यालय द्वारा राजकीय कार्यों जनहित के कार्यों हेतु जनपदों को नेटवर्क कनेक्टिविटी एवं तकनीकी उपकरणों से सुसज्जित ई-मोबाइल वैन आवंटित की गयी हैं।

उपरोक्त आदेश के क्रम में 'डॉ जगदीश चंद्र एसपी क्राइमड्रैफ्टिक नैनीताल(नोडल अधिकारी)' के पर्यवेक्षण में सूरज सिंह प्रभारी मोबाइल वैन और टीम द्वारा 'रामगढ़(भवानी) तथा मुक्तेश्वर क्षेत्र' में स्थानीय लोगों को नए आपराधिक कानूनों (बी०एन०एस०एस०, बी०एन०एस० एवं बी०एस०ए०) के प्रति जागरूक किया गया तथा ई मोबाइल वैन की उपयोगिता के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

न्यूज डायरी

बीकेटीसी उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती के नेतृत्व में बदरीनाथ धाम में हुआ पौधारोपण



बदरीनाथ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरित भारत अभियान एक पेड़ मां के नाम के तहत बीकेटीसी, वन विभाग, जिला पुलिस-प्रशासन तथा तीर्थ पुरोहितों, बामणी गांव के जागरूक लोगों द्वारा बीकेटीसी उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती के निर्देशन में वन महोत्सव के तहत बदरीनाथ धाम के निकटवर्ती स्थानों में वृक्षारोपण किया। बीकेटीसी उपाध्यक्ष ने कहा कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पर्यावरण लगातार बिगड़ता जा रहा है तथा निरंतर भूस्खलन की घटनाओं को रोकने तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु वृक्षारोपण जरूरी है। बीकेटीसी मीडिया प्रभारी डा. हरीश गौड़ ने बताया कि आज वृक्षारोपण में बांज, बुरांस, देवदार, तुलसी आदि पौधों का रोपण किया गया तथा धर्माधिकारी राधाकृष्ण थपलियाल ने वृक्षारोपण से पहले सभी पेड़ पौधों की पूजा-अर्चना की।

सचिव सहकारिता ने की राज्यपाल से भेंट



देहरादून। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) से शनिवार को राजभवन में सचिव सहकारिता डॉ. बी. वी. आर. सी. पुरुषोत्तम ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राज्यपाल ने सचिव से राज्य में सहकारिता क्षेत्र में प्रगति, योजनाओं आदि के बारे में जानकारी ली। राज्यपाल ने सहकारिता को आत्मनिर्भरता और ग्रामीण विकास का सशक्त माध्यम बताया तथा पर्वतीय क्षेत्रों में इसे और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। इस अवसर पर निबंधक सहकारिता डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट उपस्थित रहे।

ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं स्वावलंबन की ओर तेजी से हों अग्रसर: रावत

रुद्रप्रयाग (नजरिया खबर ब्यूरो)। मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत ने जनपद में संचालित ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना (रीप) एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत स्थापित ग्रोथ सेंटरों और सरस केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विकासखंड जखोली, मक्कुमठ एवं अगस्त्यमुनि स्थित प्रसंस्करण इकाइयों, प्रसाद निर्माण इकाई तथा माइनर असेंबली यूनिट का जायजा लिया।

उन्होंने निरीक्षण की शुरुआत लाटा बाबा आजीविका स्वायत्त सहकारिता द्वारा संचालित प्रसाद निर्माण इकाई से हुई, जो ब्लॉक जखोली में स्थित



सीडीओ ग्रोथ सेंटर का निरीक्षण करते हुए।

है। इसके पश्चात मुख्य विकास अधिकारी ने मक्कुमठ में फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट सेंटर का अवलोकन किया और अंत में अगस्त्यमुनि स्थित सरस माइनर असेंबली यूनिट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ग्रोथ सेंटरों में बंद पड़ी मशीनों और

उपकरणों को शीघ्र चालू करने के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि इन केंद्रों का संचालन पूर्ण रूप से सुचारु होना चाहिए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं स्वावलंबन की ओर तेजी से अग्रसर हो सकें।